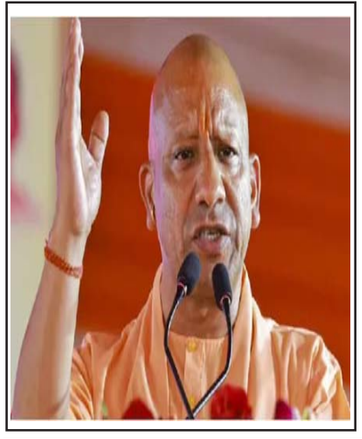

www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–44 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,सोमवार 12 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने संगम स्नान

दिया सियासी संदेश, हिंदुत्व के एजेंडे को दी धार

प्रयागराज।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेले के पावन अवसर पर अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बतौर सीएम दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब योगी ने माघ मेला के दौरान संगम स्नान किया।

प्रयागराज (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेले के पावन अवसर पर अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बतौर सीएम दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब योगी ने माघ मेला के दौरान संगम स्नान किया। सीएम योगी द्वारा माघ मेले में किए गए संगम स्नान को वर्ष 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को धार देने वाला बताया जा रहा है।वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाई थी। उस स्नान के बाद हुए चुनाव में केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी सरकार काबिज हुई थी, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एक शुभ संकेत मान रहे थे। कल के स्नान के दौरान सीएम योगी के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे तो आश्रम में कई संतों ने मुख्यमंत्री को विशेष संबोधनों से नवाजा। कुछ संतों ने 'युवा हिंदू सम्राट' तो कुछ ने 'हिंदू हृदय सम्राट' कहकर सीएम को संबोधित किया।भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बाजपेयी ने कहा कि संतों के इन संबोधनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के बाद भाजपा अपने सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ एक प्रशासनिक मुखिया के रूप पेश करेगी बल्कि हिंदुत्व के एक बड़े प्रतीक और संरक्षक के रूप में मजबूती से पेश कर सकती है।

पीएम मोदी बोले- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, 1000 साल की यात्रा के लिए है

सोमनाथ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व करोड़ों–करोड़ भारतीयों की शाश्वत आस्था, साधना और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतिबिंब है और इसका सहभागी बनना उनके जीवन का अविस्मरणीय और अमूल्य क्षण है। वह यहां आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विध्वंस नहीं बल्कि 1000 साल की यात्रा का पर्व है। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए। उसी तरह विदेश आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिशें होती रहीं लेकिन न तो सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को मिटाने की कई कोशिशें हुईं। देश के आजाद होने के बाद भी सोमनाथ पर आक्रामण को आर्थिक लूट बताया गया, ऐसा होता तो फिर पहले हमले के बाद इस नष्ट करने की कोशिश नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरदार पटेल ने जब पुर्निर्माण का संकल्प लिया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कि जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यहां आने के लिए योजना बनाई तो उन्हें भी रोका गया। मोदी ने कहा कि एक हजार साल पहले, इसी जगह पर, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने अपनी आस्था, विश्वास, महादेव के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि हजार साल पहले के आततायी सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया, लेकिन आज एक हजार साल बाद भी, सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है।

मजहबी आततायी इतिहास के पन्नों में सिमट गए तो वहीं सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इतिहास की कुछ घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कि हमलावर गजनी को लगा था कि उसने सोमनाथ मंदिर के वजूद को मिटा दिया, लेकिन 12 शाताब्दी में पुनर्निर्माण हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामण किया। इसके बाद 14वीं सदी में जूनागढ़ के राजा ने पुनर्निर्माण किया। फिर सुल्तान अहमद शाह ने दुस्साहस किया। उसके बाद सुल्तान महमूद वेगड़ा ने मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। 17वीं और 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौरा आया। उसने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश तो अहित्याबाई होलकर ने मंदिर बना दिया। मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है।

एक्स' ने अपनी गलती स्वीकार की, भारतीय कानूनों के पालन का दिया आश्वासन

नई दिल्ली 11 जनवरी (एजेंसी)सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच 'एक्स' को 'ग्रोक एआई' के अश्लील सामग्री मुद्दे पर चेतावनी दिए जाने के बाद इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, 'एक्स' ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगा। साथ ही यह भी कहा है कि भविष्य में यह मंच अश्लील छवियों की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले, सरकार ने 'एक्स' से ग्रोक एआई से जुड़ी अश्लील सामग्री पर की गई विशिष्ट कार्रवाई और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी क्योंकि इस मंच द्वारा दिए जवाब को सरकार ने अपर्याप्त पाया था।

हिजाब पर फिर गरमाई सियासत

पीएम पद को लेकर ओवैसी-हिमंत सरमा में तीखी जंग

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शहिजाब वाली प्रधानमंत्रीश वाले बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जिस पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। इस जुबानी जंग में कांग्रेस और बीजेपी भी शामिल हो गए हैं, जिससे यह विवाद संवैधानिक अधिकारों और सांप्रदायिक राजनीति के इर्द–गिर्द घूम रहा है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने इच्छा जताई कि वे एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शहमेशा एक हिंदू ही होगाश, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में केवल एक खास धर्म के व्यक्ति को ही पीएम बनने की अनुमति है, लेकिन बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान भारत के हर नागरिक को यह मौका देता है। उन्होंने कहा, शमेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने।श

हिमंत बिस्वा सरमा का जवाब

ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के सीएम ने कहा कि भले ही संविधान किसी को भी पीएम बनने से नहीं रोकता, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही बनेगा।

ओवैसी का पलटवार

रविवार को ओवैसी ने सीएम सरमा के बयान को शछोटी सोचश वाला बताया और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पीएम केवल हिंदू ही हो सकता है।इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरमा की आलोचना की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि वे एक सिख थे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मसूद ने कहा कि संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा, यह धर्म तय नहीं कर सकता।

बीजेपी ने ओवैसी को घेरा

बीजेपी के अन्य नेताओं ने ओवैसी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि ओवैसी जानबूझकर हिजाब का मुद्दा उठाकर तनाव बढ़ाना चाहते हैं।

बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तर्क दिया कि दुनिया भर में कई मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी हैं,

लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं पहना। उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी कि वे पहले अपनी पार्टी में किसी हिजाब पहनने वाली महिला को बड़े पद पर आगे बढ़ाएं।

केरला में कन्नड़ माध्यम के विद्यालयों में मलयालम थोपे जाने का सिद्धरमैया ने विरोध किया

सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि यदि केरल के राज्यपाल प्रस्तावित कानून को सहमति प्रदान करते हैं और यह लागू होता है तो कर्नाटक इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए विवश होग।

नई दिल्ली (एजेंसी)कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धरमैया ने कन्नड़ माध्यम से विद्यालयों में भी मलयालम को अनिवार्य करने के केरल सरकार के कदम का कड़ा विरोध करते हुए शनिवार को कहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती।मंगलुरु नगर के पास पिलिकुला निसर्ग धाम में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में सिद्धरमैया ने कहा कि यद्यपि एक राज्य की विधायिका कानून पारित कर सकती है, इसे लागू करने में संवैधानिक सुरक्षा और भाषाई विविधता का सम्मान करना आवश्यक है।उन्होंने कहा, ''केरल सरकार ने एक कानून पारित किया होगा, लेकिन उसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। आप भाषाई अल्पसंख्यकों पर एक जबरदस्ती थोप नहीं सकते। यह स्वीकार्य नहीं है कि अन्य मातृ भाषाएं बोलने वाले लोगों के केवल मलयालम सीखने पर जोर दिया जाए।''सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि यदि केरल के राज्यपाल प्रस्तावित कानून को सहमति प्रदान करते हैं और यह लागू होता है तो कर्नाटक इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए विवश होग। और ''यदि यह कानून बनता है तो यह स्थिति हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य करेगी। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से भी अपील की जाएगी।''मुख्यमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि भारत का संघीय ढांचा और संवैधानिक रूपरेखा, भाषाई अल्पसंख्यकों की विशेषकर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा करती है जहां समुदायों ने अपनी और संस्कृति को ऐतिहासिक रूप से संरक्षित रखा है तथा इन सुरक्षा को हल्का करने का कोई भी प्रयास एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां दक्षिण भारत में, विशेषकर भाषाई सीमाओं से सटे राज्यों में, अधिकारों और शिक्षा नीति पर बढ़ते राजनीतिक ध्यान के बीच आई हैं। अन्य प्रशासनिक मामलों पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार उन तीन कानूनों पर स्पष्टीकरण देगी जो वर्तमान में राज्यपाल की सहमति के लिए लंबित हैं। उन्होंने उन विधेयकों का नाम लिए बगैर कहा, ''राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। सरकार आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है।

आरएसएस समय के साथ विकसित हो रहा है, नए रूप धारण कर रहा है : मोहन भागवत

नई दिल्ली11 जनवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भगवत ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बदल नहीं रहा है, बल्कि समय के साथ "धीरे–धीरे विकसित हो रहा है" और "बस सामने आ रहा है"। आरएसएस प्रमुख यहां संगठन के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जो आगामी फिल्म 'शतक' के गीत संग्रह के विमोचन के लिए आयोजित किया गया था। यह फिल्म आरएसएस के 100 साल के सफर का वर्णन करती है। इस अवसर पर गायक सुखविंदर सिंह, निर्देशक आशीष मॉल, सह–निर्माता आशीष तिवारी और आरएसएस के पदाधिकारी भैयाजी जोशी उपस्थित थे। भागवत ने अपने संबोधन में कहा, "संगठन (आरएसएस) अपनी शताब्दी मना रहा है। लेकिन जैसे–जैसे संगठन विकसित होता है और नए रूप लेता है, लोग इसे बदलते हुए देखते हैं। हालांकि, वास्तव में यह बदल नहीं रहा हैय यह बस धीरे–धीरे विकसित हो रहा है।" उन्होंने कहा, "जिस प्रकार बीज से अंकुर निकलता है और फल–फूलों से लदा परिपक्व वृक्ष एक अलग रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये दोनों रूप भिन्न हैं। फिर भी, वृक्ष मूलतः उसी बीज के समान है जिससे वह उगा है।" भागवत ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार

पब्लिक में नहीं मिल सकता, होटल बुलाकर महिला का रेप करने वाले कांग्रेस के पूर्व पूर्व विधायक राहुल मामकूटथिल गिरफ्तार

कनाडा निवासी महिला की शिकायत पर पूर्व कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटथिल को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर शादी का झांसा देकर होटल में रेप करने और जबरन गर्भपात कराने जैसे संगीन आरोप हैं। पुलिस ने पीड़िता के बयानों और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के पलक्कड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मामकूटथिल को रेप और गंभीर शोषण के आरोपों के बाद रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पलक्कड़ के एक होटल से रात करीब 12रू30 बजे हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।यह कार्रवाई तब हुई जब कनाडा में रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की तीसरी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत कदम उठाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।क्या हैं महिला के गंभीर आरोप? पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए राहुल के संपर्क में आई थी। उस समय महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों से जूझ रही थी। महिला का आरोप है कि राहुल ने उसे शादी का झांसा दिया और उस पर अपनी शादी तोड़ने का दबाव बनाया।शकायत में महिला ने राहुल पर होटल के कमरे में बुलाकर बेरहमी से यौन उत्पीड़न करने, गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात के लिए मजबूर करने और पैसे हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने यह भी बताया कि जब वह बच्चे के डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रही थी, तो राहुल ने अपना सैंपल देने और जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था। धोखे से होटल बुलाकर हमला महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि जब उसने किसी सार्वजनिक जगह या रेस्टोरेंट में मिलने की बात कही, तो राहुल ने मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वह एक मशहूर व्यक्ति हैं, इसलिए बाहर नहीं मिल सकते। राहुल के कहने पर महिला ने पलक्कड़ के एक होटल में कमरा बुक किया, जहां पहुंचते ही राहुल ने उस पर हमला कर दिया और गलत काम किया।पुलिस का कहना है कि वे पीड़िता द्वारा दिए गए सबूतों और बयानों के आधार पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल मामकूटथिल को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

अदालत के आदेश पर बाराबंकी में वित्तीय घोटाले में 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कृष्णा चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी और 25 सितंबर 2025 को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बाराबकी 11 जनवरी (एजेंसी)बाराबंकी जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय के संचालन से जुड़े एक कथित वित्तीय घोटाले में अदालत के आदेश पर पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर उमाशंकर वर्मा, धीरेंद्र कुमार, मानव पटेल, मान सिंह, राजेश कुमार, राजीव, अशोक, सुनील, अजय और भागवत नाम के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।पुलिस ने बताया कि कोतवाली नगर के दशहरा बाग स्थित मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय की संस्थापक संरक्षक सदस्य कृष्णा चौधरी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रबंध समिति के कुछ अधिकारियों ने फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर संस्थान के करीब 2.7 करोड़ रुपये का गबन कर लिया है।कृष्णा चौधरी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदात में आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उमाशंकर वर्मा और सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के चुनाव कराए और रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स अयोध्या की अनुमति के बिना स्वयं को संस्थान का अधिकारी घोषित कर लिया।वादी के अनुसार पांच अप्रैल 2020 को देशव्यापी लाकडाउन के दौरान फर्जी तरीके से प्रबंध समिति की बैठक दिखाकर 17 लोगों के जाली हस्ताक्षर किए गए। इसके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा जिला सहकारी बैंक में संस्थान का खाता संचालित कर लगभग 50 लाख रुपये दयाराम एंड संस ट्रेडिंग फर्म को बिना किसी बिल के आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिए गए।आरोप है कि इसके अतिरिक्त उमाशंकर वर्मा ने अपने पुत्र मानव पटेल के खाते में बिना प्रबंध कार्यकारिणी की स्वीकृति के 20 लाख रुपये स्थानांतरित किए। इस दौरान धीरेंद्र कुमार वर्मा के जिला सहकारी बैंक के नामित चेयरमैन होने का भी लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है।कृष्णा चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। और 25 सितंबर 2025 को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में अदालत ने आवेदन पर सुनवाई कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस बीच उमाशंकर वर्मा ने कहा कि संस्था में कहीं कोई अनियमितता नहीं है।

एनपीए-निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में बारबीआई, बैंकों ने जताया विरोध

नई दिल्ली11 जनवरी (एजेंसी)बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, यस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संपर्क कर डिफॉल्टरों और एनपीए की सूची, जुर्माने और निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर आरबीआई ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत इन अभिलेखों का खुलासा किया जा सकता है। आरटीआई आवेदनकर्ताओं धीरज मिश्रा, वथिराज, गिरीश मित्तल और राधा रामन तिवारी ने आरबीआई में अलग–अलग आवेदन देकर इस बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने यस बैंक के शीर्ष 100 एनपीए और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों, एसबीआई और आरबीएल की निरीक्षण रिपोर्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा पर वैधानिक निरीक्षण के बाद लगे 4.34 करोड़ रुपये के मौद्रिक जुर्माने से संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियां मांगी थीं। इन बैंकों ने सीआईसी के पास अपील की, क्योंकि बैंकिंग नियामक आरबीआई ने पाया कि आरटीआई आवेदनकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जा सकती है। सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने बैंकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को सीआईसी की बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अंतिम निर्णय तक सूचना देने पर रोक लगा दी गई है।

संभावनाओं को नतीजों में बदल रहे योगी

- jkstxkj ds {ks= esa Hkh rsth ls c<k ;wihA
- ns'k dh thMhih esa 9-5 Qhlnh dk ;kxnkuA
- fuos'kdksa dh igyh ilan cuk ;wihA
- fMQsUl {ks= esa gh 34 djksM+ dk fuos'kA

दृढ़ इच्छाशक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। इससे संभावनाओं को नतीजों में बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़क कानून–व्यवस्था में तो नाम कमाया ही है, साथ ही उत्तर प्रदेश को रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ाया है। इसी का नतीजा है कि आज यूपी देश की जीडीपी के साढ़े नौ फीसदी का योगदान दे रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश का सकल घेरलू उत्पाद अर्थात जीडीपी 36 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। उद्योग पति प्रदेश में निवेश करने को उत्साहित दिख रहे हैं। गत 9 जनवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैण्ड कम्पनी के इलेक्ट्रिक ह्वीकल (ईवी) विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अभी इसकी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता 2500 यूनिट प्रतिवर्ष है लेकिन इसे 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था। इस प्रकार उनकी सरकार को 8 वर्ष हो चुके हैं और इन वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। अशोक लीलैण्ड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा कहते हैं कि उनका ग्रुप यूपी के 10 हजार युवकों का स्किल डेवलपमेंट करेगा। इस प्रकार यूपी को राजस्व और रोजगार दोनों मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के 34 सेक्टरों को निवेश के लिए खोल रखा है। रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की इस संदर्भ में विशेष रूप से तारीफ की है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में 34000 करोड़ रुपए का निवेश तो डिफेन्स क्षेत्र से ही आया है। उन्होंने कहा आपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दीं, उसका निर्माण भी यूपी की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के साथ गत 9 जनवरी को अशोक लीलैण्ड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और सिंदूर–रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे। सीएम योगी ने निवेश के लिए हिंदुजा परिवार को शुभकामनाएं दीं और यूपी सरकार पर विश्वास के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि यूपी के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 के पहले यूपी की अराजकता किसी से छिपी नहीं थी, निवेशक पलायन कर रहे थे परंतु 2017 में सरकार में आने पर हमने कहा कि यह अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया, लेकिन यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन गया है। पिछले आठ–साढ़े आठ साल में हुआ परिवर्तन इसका उदाहरण है। यह समारोह प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि जब दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग व ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम आपदाएं चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस दिशा में किए जाने वाला प्रयास का एक हिस्सा है। इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं।

सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। सीएम ने बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए बताया कि देश के एक्सप्रेस वे का 55 फीसदी एक्सप्रेस वे यूपी के पास है। देश में सर्वाधिक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों व मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। देश में बन रहे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी से होकर जा रहे हैं। इन पर यूपी का लॉजिस्टिक टर्मिनल व लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य हो रहा है। देश में पहली रैपिड रेल व वाटर वे का संचालन भी यूपी में हो चुका है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि इसने खुद को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। दृढ़ निश्चय से लिए गये फैसले, साफ नीयत व स्पष्ट सोच के कारण फियरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नए यूपी की पहचान बन चुके हैं। यहां पर कोई निवेशक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं हो सकता। यूपी में अब 34 सेक्टोरियल पॉलिसी हैं, जिनके माध्यम से निवेशक किसी भी सेक्टर में निवेश करके यूपी की विकास यात्रा में योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी के विजन–2047 का जिक्र किया और कहा कि हर देशवासी ने भारत को विकसित–आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। यह प्लांट मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के संकल्प को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यूपी आज इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर्स फर्स्ट के दृष्टिकोण से देश–दुनिया के हर निवेशकों का महत्वपूर्ण पसंदीदा स्थल बन चुका है। पिछले 8–9 वर्ष में यूपी में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए। इसमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अगले महीने छह लाख करोड़ के अन्य निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी। पांच लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में और हैं, जिनकी यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग कराई जाएगी।

सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। यूपी की जीएसडीपी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 36 लाख करोड़ की हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन व बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ यूपी एक लक्ष्य लेकर चला है। प्रधानमंत्री ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के रूप में बदलने को कहा है तो हमने भी लक्ष्य तय किया है कि 2029–30 में यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व आईटी हब बनने की राह पर तेजी से बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55 फीसदी यूपी में बन रहा है। देश के 60 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूपी में बन रहे हैं। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर है। एमएसएमई, एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स, ईवी, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थटेक, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग व खोल जैसे क्षेत्र में यूपी तेज गति से आगे बढ़ा है। यूपी में 18 हजार से अधिक स्टार्टअप हैं। यहां 76 इन्क्यूबेटर्स, सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व 8 यूनिकॉर्न कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अशोका लेलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एफडीआई व फॉर्च्यून–500 पॉलिसी का हिस्सा है। 2017 के पहले यूपी में एफडीआई का अंश ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था, लेकिन आज यूपी ने अपनी पॉलिसी के माध्यम से एफडीआई व फॉर्च्यून–500 को आकर्षित किया है। (हिफी)

सम्पादकीय

सत्य का अंतिम सत्य संकल्प, साहस, श्रम और सफलता

सत्य का अंतिम रूप साहस, श्रम और सफलता से होकर गुजरता है और यह बात पूर्णतः सही है कि सत्य परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं, क्योंकि यदि सत्य और सच्चाई न होती तो मानव जीवन का अस्तित्व ही संभव न होताय पहाड़, झरने, नदियाँ, जंगल, पृथ्वी और प्रकृति के संतुलन से लेकर मनुष्य और अन्य जीवों तक सब कुछ प्राकृतिक सत्य की ही उपज है, परंतु यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य अपने लालच, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थ के कारण त्वरित लाभ पाने के लिए झूठ, छल और दिखावे का सहारा लेकर जीवन की गहराइयों में उतर जाता है, जबकि अंततः सत्य ही अंतिम विजय प्राप्त करता है, किंतु आज की परिस्थितियों में सच्चाई जीवन के लगभग हर क्षेत्र से दूर होती जा रही है और जब हम स्वयं भ्रम में जी रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम कौन से नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य सौंप पाएंगे, यह एक गंभीर प्रश्न बन गया हैय आज के उत्तर आधुनिक समाज में उपभोक्तावादी सोच इतनी हावी हो चुकी है कि भौतिक साधनों और सुखों की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान ली गई है, जिसके लिए झूठ, फरेब और साजिशें सामान्य व्यवहार बनती जा रही हैं, जबकि प्राचीन समय में समाज आत्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित था, पर विकास की बदली हुई परिभाषा ने समाज को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ भौतिकता सर्वोपरि हो गई है और इसके परिणामस्वरूप आपसी रिश्तों की गर्माहट, भरोसा और संवेदनशीलता तेजी से समाप्त होती जा रही हैय आज स्थिति यह है कि सत्य बोलना एक सामान्य आचरण न होकर कठिन साधना जैसा हो गया है, जबकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन और विचारों में सत्य और अहिंसा को ही सामाजिक और नैतिक उत्थान का आधार माना था और उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान हो जाए तो समाज अपने आप ऊँचे स्तर तक पहुँच सकता है, क्योंकि सत्य और संयम व्यक्ति को आत्मबल, स्वाभिमान और आत्मसम्मान प्रदान करते हैं, वहीं असत्य मनुष्य को भीतर से कमजोर और अपराधबोध से ग्रस्त करता हैय कबीरदास जैसे संतों ने भी सत्य को ईश्वर के समान माना और समाज को झूठ से दूर रहने की सीख दी, क्योंकि झूठ केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को विकृत करता है और यही कारण है कि असत्य को सभी बुराइयों की जड़ माना गया है, आज भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते केवल औपचारिक बनकर रह गए हैं और मनुष्य अपनी सुविधा और सफलता के लिए बिना संकोच झूठ का सहारा ले रहा है, जिससे सामाजिक व्यवहार में असंवेदनशीलता और अविश्वास बढ़ता जा रहा हैय नैतिकता और अनैतिकता के बीच की महीन रेखा को पहचानने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है और मनुष्य किसी भी साधन को सही ठहराने लगा है यदि उससे उसे लाभ मिलता हो, परिणामस्वरूप समाज में असंतुलन, विघटन और संबंधों का क्षय साफ दिखाई देता हैय इतिहास भी गवाह है कि जब–जब समाज ने सत्य और नैतिकता से दूरी बनाई है तब–तब पतन की प्रक्रिया तेज हुई है, आज जब भौतिक संपन्नता को ही सफलता का मापदंड बना लिया गया है ।

दिल्ली में अवैध नागरिकों पर शिकंजा

मतदाताओं का विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) का मुख्य उद्देश्य अवैध नागरिकों की पहचान करना है। इस मामले में देश भर में कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की धर–पकड़ तेज कर दी है। गत 8 जनवरी को ही दिल्ली के भीतर 20 बांग्लादेशी नागरिौं को पकड़ा गया। छानबीन के बाद पता चला कि ये सभी अवैधा रूप से भारत में रह रहे थे। दिल्ली में इससे पहले भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी पकड़े गये थे। पिछले वर्ष 25 सितम्बर को 25 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। उनको दक्षिणी दिल्ली से पकड़ा गया था। उसी दौरान त्रिपुरा के गोमती जिले में पुलिस ने पांच बांग्लादेशी कामगारों को हिरासत में लिया था। वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 19 सितम्बर 2025 को बताया था कि बांग्लादेशी नागरिक निर्माण और फर्नीचर का काम कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा कहते हैं कि ऐसे ही हालात रहे तो असम बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने यह बात दिसम्बर 2025 में कही थी। बहरहाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल बाहर करने पर आमदा हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के भीतर 20 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस द्वारा 20 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैधा रूप से भारत में रह रहे थे। पकड़े गए अवैध लोगों के पास से कुछ भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं।भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द ही दिल्ली में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराया जाएगा। दिल्ली में ये प्रक्रिया तीसरे चरण में होगी। चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के एसआईआर का आयोजन बिहार में कराया गया था। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में पिछली बार जब एसआईआर हुआ था, उसे 20 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं। इसलिए अब वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी हो गया है। अन्य राज्यों से मिले उदाहरण से ऐसी संभावना दिख रही है कि दिल्ली में भी लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट से नाम बाहर किए जा सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका निधन हो गया हो।

इससे पूर्व भी दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशियों को दक्षिण दिल्ली से पकड़ा था। उन्हीं दिनों त्रिपुरा के गोमती जिले में पुलिस ने पांच बांग्लादेशी कामगारों को हिरासत में लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने 19 सितंबर 2025 को इस बारे में जानकारी दी थी। अधिकारी के अनुसार, ये सभी बांग्लादेशी नागरिक महारानी इलाके में निर्माण और फर्नीचर का काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे कुछ दिन पहले ही भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। उदयपुर की उप–मंडलीय पुलिस अधिकारी देबांजलि रे ने बताया कि महारानी इलाके में तलाशी के दौरान पुलिस ने एक ऑटो–रिक्शा को रोका। पूछताछ में शक होने पर पांचों यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया। देबांजलि रे ने बताया था, पांचों मजदूरों को पश्चिमी त्रिपुरा में स्थित राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक आश्रय गृह में भेज दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने इन्हें वापस भेजने के लिए बांग्लादेशी समकक्षों से बात की थी।

उधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर असम में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों की आबादी में 10 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होती है तो असम स्वयं ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। बता दें कि सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने बीते दिसम्बर ये बात एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा कि वह बीते पांच सालों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। दरअसल, सीएम हिमंत विश्व शर्मा से बांग्लादेश के एक नेता की उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया था जिसमें उस नेता ने पूर्वोत्तर का पड़ोसी देश में विलय करने की बात कही थी। इस पर सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने कहा– असम में 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर यह संख्या 10 प्रतिशत और बढ़ जाती है तो हम स्वतः ही इसमें शामिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं पिछले पांच वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं।दरअसल, दिसंबर महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में गठित एक नए राजनीतिक दल– नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के एक नेता हसनत अब्दुल्ला ने कथित तौर पर कहा था कि बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 'अलग–थलग कर देना चाहिए। हसनत अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि ढाका को क्षेत्र में अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए। असम के कामरूप जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। युवक पर बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीटकर हत्या के

समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप थे। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार युवक ने हिंदू युवक की हत्या का वीडियो कथित तौर पर पोस्ट किया और इस अपराधा के समर्थन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था।दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव के तहत अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 6 बांग्लादेशी नागरिक, 5 भारतीय सहयोगी और कुल 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेशी दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, मोबाइल सिम कार्ड बराकद हुए थे।आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशों को बसाने और रोजगार दिलाने का आरोप है।दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना चांद मियां है, जो खुद बांग्लादेशी है और भारत में अवैध रूप से 5 साल की उम्र से रह रहा है। पुलिस के मुताबिक चांद मियां पिछले तकरीबन 5 साल से भारत में अवैध बांग्लादेशियों को बनाने का रैकेट चला रहा है। चांद मियां पश्चिम बंगाल, मेघालय और बेनापोल सीमा के जरिए बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करवाता था।

दुनिया के लिए मुसीबत बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

Mkनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अमेरिकी जनता से यूक्रेन युद्ध रुकवाने का वादा किया था। लेकिन नया साल शुरू होते ही उनके कदम दुनिया में शांति के बजाय तनाव और टकराव को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि मिडिल ईस्ट में आग भड़क चुकी है। इस बीच अब अमेरिका–रूस के बीच सीधा टकराव वैश्विक चिंता का कारण बन गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं?हाल ही में अमेरिका ने उत्तारी अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर 'मरीनेरा' को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में की गई। अमेरिकी दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था। यह वही टैंकर है जिसका पुराना नाम 'बेला–1' था और जिस पर 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। बाद में इसका नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया गया।

आपको बता दें अमेरिकी साम्राज्यवाद, जिसे अक्सर सैन्य विस्तार, आर्थिक प्रभुत्व और सांस्कृतिक प्रभाव के मिश्रण के रूप में समझा जाता है, आज प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद की जगह नीतिगत दबाव, वैश्विक संस्थानों, तकनीकी व वित्तीय ताकत के जरिए संचालित होता है। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत एक ओर उभरती महाशक्ति है, तो दूसरी ओर अपने ऐतिहासिक गुटनिरपेक्ष रुख और रणनीतिक स्वायत्तता पर गर्व करता है। बहरहाल, भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ऐसी ढलान पर हैं जहां तनाव हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी और टेरिफ बढ़ाने की धामकियां अब सिर्फ जुबानी नहीं रही। बात अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गई। दरअसल अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा कानून आने वाला है जो भारत के लिए काफी भारी पड़ सकता है। वो ऐसे कि अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025 लाने की तैयारी है। यह बिल अमेरिका के दो सीनेटरों– लिंसे ग्राहम और रिचर्ड लुमथन ने मिलकर तैयार किया है, जिसे व्हाइट हाउस की हरी झंडी मिल चुकी है। मकसद साफ है रूस की आर्थिक नसों को काटना लेकिन इसकी चपेट में भारत भी आता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से जमकर सस्ता कच्चा तेल खरीदा है लेकिन अब अमेरिका इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस नए बिल के तहत एक बेहद खतरनाक प्रावधान जोड़ा गया है। अगर रूस शांति वार्ता के लिए नहीं झुकता तो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500 प्रतिशत तक का टेरिफ लगा सकता है। भारत पर अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल को लेकर अतिरिक्त टेरिफ लगाए हैं। दूसरी ओर, लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक तनाव के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ व्यवहार में सावधानी बरती है। इसका एक प्रमुख कारण दुर्लभ खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घटकों, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर बीजिंग का प्रभुत्व है। भले ही चीन रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, लेकिन उस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाए गए हैं। इसके बजाय, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी आयात पर नए शुल्क को स्थगित कर दिया, जिससे शुल्क 30 प्रतिशत पर बना रहा, जो भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क से काफी कम है। इसके विपरीत, भारत के पास चीन जैसी रणनीतिक ताकत नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नई दिल्ली रियायती दरों पर रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया है, लेकिन महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन की तरह उसका कोई दबदबा नहीं है। ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों पर बार–बार असंतोष जताया है और नई दिल्ली पर अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क और बाधाएं बनाए रखने का आरोप लगाया है। कुल 50 प्रतिशत के ये शुल्क भारत द्वारा रूसी तेल की भारी मात्रा में खरीद के कारण लगाए गए हैं, जिसे अमेरिका यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाला मानता है। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए उच्च शुल्क को लेकर प्रधानमंत्री मोदी नाखुश हैं। हाउस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की बैठक में ट्रंप ने कहा कि हालांकि संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन शुल्क के मुद्दे ने तनाव पैदा कर दिया है। आपको पता रहे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का स्वरूप अक्सर नियम–निर्माण के माध्यम से दिखाई देता है, जिनमें व्यापार शर्तें, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल शासन, और वित्तीय संस्थानों में प्रभाव शामिल है। भारत पर कभी–कभी व्यापार घाटे, डेटा स्थानीयकरण, दवा पेटेंट या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर दबाव देखा गया है। प्रतिबंधों की राजनीति और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था भी विकासशील देशों की नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। सांस्कृतिक स्तर पर भी अमेरिकी प्रभाव, हॉलीवुड, उपभोक्तावाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म–भारतीय समाज में आकांक्षाओं और जीवनशैली को प्रभावित करता है। यह प्रभाव अपने साथ अवसर और जोखिम दोनों लाता है– नवाचार, अभिव्यक्ति और वैश्विक जुड़ाव के अवसर, पर साथ ही स्थानीय भाषाओं, कलाओं और श्रम–संरचनाओं पर दबाव भी। ऐसे में, भारत की चुनौती यहां संतुलन साधने की है। एक ओर चीन जैसी आक्रामक शक्ति के बीच अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर, किसी एक शक्ति ध्रुव पर अत्यधिक निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। इसलिए भारत बहुध्रुवीय विश्व का समर्थक रहा है, जहां अमेरिका, यूरोप, रूस, एशिया और वैश्विक दक्षिण सभी की भूमिका हो। नीति–निर्माण में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण क्षमता, तकनीकी नवाचार और दक्षिण–दक्षिण सहयोग जैसे कदम अमेरिकी प्रभुत्व के संभावित नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं। साथ ही, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानवाधिकारों पर भारत का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। बदलते वैश्विक माहौल में अमेरिका खुद दुनिया के सामने मुसीबत के बीज बो रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प इस सारे विवाद को जन्म दे रहे हैं। ¼fgQh½

बीसीसीआई ने किया गड़बड़झाला

बीसीसीआई ने गड़बड़झाला किया। क्या अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत को बांग्लादेश से क्रिकेट संबंध तोड़ लेना चाहिए? बीसीसीआई ऐसा सोचती है, तो फिर उसने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल नीलामी में क्यों शामिल किया?

टी–20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत ना आने का बांग्लादेश का एलान क्रिकेट और भारत दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर हुए विवाद के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से बांग्लादेश के सारे मैच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सह–मेजबान श्रीलंका में कराने की मांग की है। आईसीसी ने ये मांग मानी (या मांग ना माने जाने की स्थिति में बांग्लादेश ने टूर्नामेंट का बहिष्कार किया), तो उसका दूरगामी असर होगा। यह साफ है कि रहमान के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गड़बड़झाला किया। उसने उन्हें उन खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा, जिन्हें आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमें खरीद सकती थीं।कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने उन्हें खरीदा, तो एक भाजपा नेता और इस दल के समर्थक समूहों ने टीम के मालिक अभिनेता शाहरुख खान पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। उन्हें गद्दार तक कहा गया। बेशक, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय इस समय निशाने पर है। उसको लेकर भारत के बहुसंख्यक समुदाय का नाराज होना लाजिमी है। लेकिन मुद्दा है कि क्या इसको लेकर भारत को बांग्लादेश से क्रिकेट संबंध तोड़ लेना चाहिए? बीसीसीआई ऐसा सोचती है, तो फिर उसने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल नीलामी में क्यों रखा? उसके बाद राजनीतिक कारणों से किसी समूह विशेष ने भड़काऊ माहौल बनाया, तो क्या यह उचित नहीं होता कि बीसीसीआई अपने रुख पर कायम रहती और केकेआर को उचित संरक्षण देती?लेकिन उसने रहमान को टीम से हटा देने की सलाह दी, जिस पर केकेआर ने फौरन अमल किया। उस पर बीसीबी ने भी उग्र प्रतिक्रिया दिखाई है। नतीजतन, सात फरवरी से शुरू हो रहे टी–20 वर्ल्ड कप से एक नया विवाद जुड़ गया है। भारत और पाकिस्तान के एक– दूसरे के यहां ना जाने के फैसलों की आंच पहले से ही क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर पड़ी हुई है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के छठे स्थापना दिवस पर भव्य समारोह, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 पुलिसकर्मी सम्मानित

लखनऊ(संवाददाता) पुलिस कमिश्नरेट के छठे स्थापना दिवस के अवसर पर 11 जनवरी 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन परिसर, महानगर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव कृष्णा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के पूर्व पुलिस आयुक्त ध्रुवकांत ठाकुर, पुलिस महानिदेशक एसएसएफध्नागरिक सुरक्षा पद्म शिरडकर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश, पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेंद्र कुमार सेंगर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।समारोह के दौरान साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं, कानून–व्यवस्था और प्रशासनिक दायित्वों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 150 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने 19 पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में बड़े खाने का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी तथा पुलिस लाइन और सभी थानों में कार्यरत पुलिसकर्मी शामिल हुए। पूरे आयोजन में उत्साह, गर्व और आत्मविश्वास का वातावरण देखने को मिला।उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुदृढ़, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 13 जनवरी 2020 को लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। यह निर्णय प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जाता है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद बीते छह वर्षों में लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक और गुणात्मक सुधार दर्ज किया गया है। अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है और हत्या, लूट एवं डकैती जैसी संगीन घटनाओं में निरंतर कमी आई है। विशेष रूप से वर्ष 2025 में लखनऊ जनपद में डकैती की एक भी घटना न होना कमिश्नरेट व्यवस्था की प्रभावी कार्यशैली, सतर्कता और मजबूत सुरक्षा तंत्र का प्रमाण माना जा रहा है।महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सेफ सिटी की अवधारणा को मजबूती से लागू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और महिला संबंधी अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जिसे महिला सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में भी कमिश्नरेट द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। मृतक आश्रितों को नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का त्वरित निस्तारण, पीएसपी पैकेज के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान, बैरक और हॉस्टल, आवासीय भवनों का निर्माण, छह नए पुलिस थानों के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन तथा 700 महिला रिक्रूट आरक्षियों के लिए हॉस्टल और अकादमिक ब्लॉक का संचालन किया गया है।समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि लखनऊ पुलिस की उपलब्धियों का श्रेय बल के अनुशासन, साहस और कर्तव्यनिष्ठा को जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के बाद लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराध को तकनीकी प्राथमिकता के रूप में विकसित किया है। इसके तहत समर्पित साइबर क्राइम थाना, साइबर सेल और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। साइबर अपराध की बदलती प्रकृति को देखते हुए उप निरीक्षकों को विशेष रूप से साइबर ठगी में धन की त्वरित रोकथाम और आईटी एक्ट से संबंधित विवेचनाओं के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया।

उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति केंद्रों और पिंक बूथों पर तैनात पुलिसकर्मी महिला सुरक्षा के साथ–साथ ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर लाभान्वित करा रहे हैं। साथ ही सभी आरटीसी केंद्रों पर पीपीटी और तकनीकी माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण एकीकृत प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि भविष्य की पुलिसिंग स्मार्ट, संवेदनशील और जन–विश्वास पर आधारित होगी।

बीबीएयू में विश्वविद्यालय दिवस पर 'विकसित भारत' के संकल्प को लेकर सामाजिक परिवर्तन का आह्वान

लखनऊ(संवाददाता) स्थित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 11 जनवरी को तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह के अंतर्गत 'विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि हेतु सामाजिक परिवर्तन का आह्वान' विषय पर द्विसत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य डॉ. चमन लाल बंगा, आयोजन समिति के संयोजक एवं शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही तथा डॉ. बुद्धि सागर गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा महात्मा गौतम बुद्ध और बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। विश्वविद्यालय कुलगीत के पश्चात आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का पौधा, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रो. राजशरण शाही ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया, जबकि मंच संचालन का दायित्व डॉ. बुद्धि सागर गुप्ता ने निभाया।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने आयोजन समिति को सार्थक और विचारोत्तेजक कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में शिक्षण, अधिगम, शोध और विस्तार गतिविधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव, अवसाद और अशांति जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में समस्त विश्व की आशा भारत की ओर है। इसका प्रमुख कारण भारतीय युवाओं की अपार शक्ति और कार्यक्षमता है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित राष्ट्र बनने की आधारशिला बताते हुए युवाओं से पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, रिड्यूस, रियूज और रीसायकल के सिद्धांत को अपनाने, स्वदेशी को बढ़ावा देने और 'वोकल फॉर लोकल' को सशक्त करने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं को नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की प्रेरणा दी।प्रदेश हिन्दी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त ने 'विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि हेतु सामाजिक परिवर्तनरू स्वभाषा की भूमिका' विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भाषा और संस्कृति के बिना किसी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने स्वभाषा में कार्य करने और उस पर गर्व करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि स्मृति, संस्कृति, पहचान और मौलिक चिंतन का आधार है। उन्होंने भारतेन्दु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय और अज्ञेय जैसे साहित्यकारों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सांस्कृतिक गुलामी की शुरुआत भाषायी गुलामी से होती है, जिससे समाज सृजनकर्ता के बजाय अनुकरणकर्ता बन जाता है।उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने स्वदेशी और स्वबोध की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के बिना चेतना को आलोकित नहीं किया जा सकता। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को वास्तविक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए स्वभाषा, स्वकर्तव्य और स्वबोध को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर गंभीर कार्य करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।अम्बेडकर फाउंडेशन के सदस्य डॉ. चमन लाल बंगा ने सामाजिक परिवर्तन में समरसता के महत्व पर विचार रखते हुए कहा कि केवल आर्थिक विकास से राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसके लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी आवश्यक है। उन्होंने समरसता को देश की प्राणशक्ति बताते हुए कहा कि जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर राष्ट्रहित में कार्य करते हैं, तभी समावेशी और संतुलित विकास संभव हो पाता है।संगोष्ठी के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता आयोजन समिति के चेयरपर्सन प्रो. राम चंद्रा ने की। इस सत्र में इतिहासवेत्ता और सामाजिक चिंतक संजय श्री हर्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के भू–विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुव सेन सिंह सहित अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे। संजय श्री हर्ष ने कर्तव्य बोध और परिवार प्रबोधन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा उसकी पारिवारिक व्यवस्था में निहित है, जहां से मूल्यबोध और संस्कारों का विकास होता है। प्रो. ध्रुव सेन सिंह ने पर्यावरण को विकास की अनिवार्य शर्त बताते हुए जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर बल दिया।कार्यक्रम चेयरपर्सन प्रो. राम चंद्रा ने कहा कि विद्यार्थी ही भविष्य के निर्माता हैं और उन्हें प्रकृति, ज्ञान और संतुलन के मूल मंत्र को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया।

अंत में प्रो. हरिशंकर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में 10 से 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विद्यार्थियों द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

लखनऊ में टिकैत राय लेबर कालोनी क्षेत्र की जलापूर्ति 12 जनवरी की शाम रहेगी प्रभावित

लखनऊ (संवाददाता)नगर निगम के जलकल विभाग ने नागरिकों को सूचित किया है कि शहर के टिकैत राय लेबर कॉलोनी क्षेत्र में स्थित ओवरहेड टैंक की नियमित सफाई का कार्य 12 जनवरी 2026, सोमवार को कराया जाएगा। इस आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण उसी दिन सायंकाल के समय क्षेत्र की जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है।जलकल विभाग के अनुसार, ओवरहेड टैंक की समय–समय पर सफाई जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। प्रस्तावित सफाई कार्य के चलते टिकैत राय लेबर कॉलोनी, सुप्पा रैस, बड़ा तालाब कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में शाम के समय पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है।नगर निगम ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे संभावित असुविधा से बचने के लिए पहले से आवश्यक तैयारी कर लें। विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि 12 जनवरी को प्रातःकाल प्राप्त होने वाली जलापूर्ति से अपनी आवश्यकता के अनुसार पेयजल का भंडारण कर लें, ताकि शाम के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जलकल विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि शहर के करेहटा और अम्बेडकर नगर क्षेत्र में स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई का कार्य 10 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान सभी सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया गया।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

लखनऊ(संवाददाता) बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार बढ़ते हमलों, मंदिरों को निशाना बनाए जाने, महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही अमानवीय बर्बरता तथा भय के माहौल में कराए जा रहे जबरन पलायन के विरोध में रविवार को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस व्यापक आंदोलन के माध्यम से पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी और विदेश नीति को पूरी तरह विफल बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट किया कि हिंदुओं के खून पर अब खामोशी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।लखनऊ में स्वास्थ्य भवन, कैसरबाग के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती और बल प्रयोग किया, जिससे धक्का–मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी ने पुलिस की इस कार्रवाई को तानाशाही और दमनकारी करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की हर कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा।राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार न तो कोई कूटनीतिक दबाव बना रही है और न ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई ठोस पहल कर रही है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार की यह चुप्पी अत्याचारियों के हौसले बढ़ा रही है, जिससे बांग्लादेश में हालात और अधिक भयावह होते जा रहे हैं।इस अवसर पर अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और प्रधानमंत्री आंख मूंदकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल विदेश नीति की विफलता नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। जब एक ओर हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तब दूसरी ओर भारत सरकार का मौन रहना नैतिक पतन का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने अब भी कठोर और निर्णायक कदम नहीं उठाए, तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा उग्र रूप देगी।प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे खूनखराबे, मंदिरों के विध्वंस और महिलाओं–बच्चों पर जारी बर्बरता के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी कोई भूल नहीं, बल्कि सोची–समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि यह चुप्पी अडानी के हजारों करोड़ रुपये के बिजली कारोबार की कीमत पर खरीदी गई है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन–चुनकर मारा जा रहा है, उसी देश को भारत से अडानी के माध्यम से बिजली सप्लाई की जा रही है और मुनाफा कमाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि यदि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके मित्र का कारोबार प्रभावित होगा,

एसआईआर के आंकड़ों पर अखिलेश यादव का सवाल, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप

लखनऊ(संवाददाता) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर और वोट लूट के कथित समीकरण को सामने रखते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही समय पर केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया, वहीं राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही प्रक्रियाएं हर जगह एक ही बीएलओ के माध्यम से कराई गईं।अखिलेश यादव ने कहा कि इसके बावजूद दोनों एसआईआर के नतीजे एक–दूसरे से बिल्कुल उलट सामने आए। विधानसभा चुनाव के एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2.89 करोड़ कम होकर केवल 12.56 करोड़ रह गई, जबकि पंचायत चुनाव के एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रक्रिया, समय और जिम्मेदार अधिकारी एक ही थे, तो आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है।उन्होंने कहा कि सीधा सवाल चुनाव आयोग से है कि दोनों में से कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि ये दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में वोट लूट का जो गणित तैयार किया गया था, उसमें संतुलन बनाना भूल गए और अब पूरी पोल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े इस तरह के विरोधाभासी आंकड़े लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिनका जवाब जनता को मिलना चाहिए।

लखनऊ में बंद घरों को निशाना बनाने वाला खतरनाक गिरोह धराया, भारी मात्रा में हथियार, बम और चोरी का माल बरामद

लखनऊ(संवाददाता) पुलिस कमिश्नरेट के उत्तरी जोन में अपराध शाखा लखनऊ और थाना मड़ियांव की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बंद घरों की रेकी कर ताले तोड़कर चोरी करने वाले चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से न केवल पीली और सफेद धातु के कीमती आभूषण और नगदी बरामद की, बल्कि अत्यंत गंभीर बात यह रही कि उनके पास से अवैध पिस्टल, तमंचे, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और आठ सुतली बम भी मिले, जिससे इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।दिनांक 11 जनवरी 2026 को अपराध शाखा और थाना मड़ियांव की पुलिस टीम प्ड तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर अपराधी बंद घरों में चोरी कर भारी मात्रा में चोरी का माल लेकर एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से दुबग्गा की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बताए गए वाहन को रोका और उस पर सवार चार व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।पूछताछ में अभियुक्तों ने अपनी पहचान नवाब अली उर्फ सलमान अली उर्फ अर्जुन उर्फ अमन, आफताब, अफरोज उर्फ मोहम्मद फिरोज और शमशुल के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से सोने–चांदी के आभूषणों का बड़ा जखीरा, दस हजार रुपये नकद, चोरी में प्रयुक्त लोहे की रॉड, चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल के साथ–साथ दो अवैध पिस्टल, दो अवैध तमंचे, कुल 23 जिंदा कारतूस और आठ सुतली बम बरामद किए गए। बरामद आभूषणों और मोटरसाइकिल के संबंध में मड़ियांव, ठाकुरगंज, दुबग्गा और बीकेटी थानों में पहले से दर्ज चोरी के मुकदमों से उनका संबंध पाया गया।पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे बंद मकानों की रेकी कर ताला तोड़कर सोने–चांदी के आभूषण चुराते थे और उन्हें राहगीरों के माध्यम से बेचकर अपने शौक पूरे करते थे। साथ ही पकड़े जाने की स्थिति में पुलिस या लोगों से बचने के लिए अवैध हथियार और सुतली बम अपने पास रखते थे। यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि यह गिरोह केवल चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि किसी भी समय गंभीर हिंसक वारदात को अंजाम दे सकता था।पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं के साथ आयुध अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कई मुकदमे पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामदगी के आधार पर अलग–अलग अभियोग दर्ज किए गए हैं ।

और अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों से भी जुटाई जा रही है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में संगठित चोरी और हथियारबंद अपराध पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से कई लंबित चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है और आने वाले समय में इससे जुड़े अन्य अपराधों की परतें भी खुल सकती हैं।

लखनऊ में ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, 1289 सीसीटीवी खंगालकर तीन हत्यारोपी गिरफ्तार

लखनऊ(संवाददाता) पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी जोन अंतर्गत थाना विकासनगर पुलिस ने एक जघन्य ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने लगभग 1289 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर न केवल हत्या की गुत्थी सुलझाई, बल्कि लूट की घटना में शामिल सभी आरोपियों को भी पकड़ लिया।यह मामला 30 दिसंबर 2025 का है, जब डायल 112 पर सूचना मिली कि विकासनगर मोड़ पर एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तत्काल डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर कूचकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान लालाराम उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम चन्देसुवा, थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर के रूप में हुई। लालाराम लाई–चना बेचने का काम करता था और विकासनगर मोड़ के पास सड़क किनारे ठेला लगाकर रात में वहीं सो जाता था।मृतक की पत्नी किरन देवी की तहरीर पर थाना विकासनगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने जमीनी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचनाओं और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने 11 जनवरी 2026 को इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया।पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्तों का मृतक से पूर्व में विवाद था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने साजिश रची, मृतक के सोने के स्थान की रेकी की और सुनसान समय का फायदा उठाकर ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

क्षत्रिय पुरोधा श्रद्धांजलि समारोह में गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को किया गया नमन

लखनऊ(संवाददाता) में 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्षत्रिय लोक सेवक परिवार महासमिति द्वारा आयोजित क्षत्रिय पुरोधा श्रद्धांजलि समारोह में क्षत्रिय समाज की गौरवशाली परंपरा, शौर्यपूर्ण इतिहास, त्याग, बलिदान और समाज सेवा को भावपूर्ण ढंग से स्मरण किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस वीर परंपरा को नमन करने का क्षण है, जिसने सदियों से राष्ट्र और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज ने न केवल रणभूमि में मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि नीति, मर्यादा, न्याय और कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श भी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उनके त्याग और बलिदान आज भी जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।सभापति ने स्पष्ट किया कि बहादुरी को किसी जाति या धर्म के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। देश का हर नागरिक जो मातृभूमि की रक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, वही सच्चे अर्थों में क्षत्रिय है। ऐसे पराक्रमी वीरों को स्मरण करना हम सबका परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि महासमिति द्वारा इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत एक अनूठी पहल है, जिससे जहां हम अपने पुरोधाओं को याद करेंगे, वहीं आने वाली पीढ़ियों को भी गौरवशाली अतीत से जोड़ा जा सकेगा। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि क्षत्रिय समाज ने हर कालखंड में लोक सेवक और राष्ट्रनायक की भूमिका निभाते हुए देश को विपदाओं से बचाया और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया।महासमिति के अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि आज समाज अपने पूर्वजों को भूलता जा रहा है। यदि हम उन्हें याद नहीं करेंगे, तो उनका नाम केवल हमारे ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की स्मृति से लुप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि वह किन महान पूर्वजों की वंशज है। इसी उद्देश्य से महासमिति ने इस वर्ष से क्षत्रिय पुरोधा श्रद्धांजलि समारोह की परंपरा शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाले 25 क्षत्रिय पुरोधाओं को प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि दी जाएगी।कार्यक्रम में साहित्यकार पद्मश्री विद्याबिन्दु सिंह ने कहा कि पितृ ऋण की परंपरा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। पुरोधाओं को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देना इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का सार्थक प्रयास है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों को जान सकेंगी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, छत्तीसगढ़ की प्रोफेसर लवली शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं और ऐसे समारोहों में आमंत्रित होकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह ने कहा कि समर्पण और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए जो अमूल्य योगदान दिया है, उसे स्मरण करने की यह पहल भविष्य में और भी मजबूत होगी और नई पीढ़ी इतिहास में दर्ज अपने पुरोधाओं को याद रखेगी।महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय पुरोधाओं द्वारा दिए गए योगदान को विशेष रूप से स्मरण किया गया और उनके वंशजों को सम्मानित किया गया। यूपी कॉलेज वाराणसी के संस्थापक उदय प्रताप सिंह के परिवारीजनों रानी सुभाश्री देवी और प्राचार्य डीके सिंह, आरबीएस कॉलेज आगरा के संस्थापक राजा बलवंत सिंह के परिवारीजन युवराज अंबरीश सिंह और प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव, टीडी कॉलेज जौनपुर के संस्थापक तिलकधारी सिंह से जुड़े प्रधानाचार्य डॉक्टर एसपी सिंह तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के संस्थापक वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती सिंह के योगदान को स्मरण करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति लवली शर्मा को सम्मानित किया गया।समिति के शिव शरण सिंह, देवराज सिंह, कार्यक्रम की संयोजक आराधना सिंह, डॉक्टर अनुपमा सिंह, डॉक्टर उर्मिला सिंह, इंजीनियर एसएन सिंह, रीता सिंह, मुसाफिर सिंह और रामनायक सिंह को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह, अनिल त्रिपाठी, विशाल सिंह, रामेंद्र सिंह, कुंवर प्रदीप, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसकेडी अकादमी के संस्थापक एसकेडी सिंह ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।इससे पूर्व समारोह की शुरुआत 25 क्षत्रिय पुरोधाओं के चित्रों पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। श्रद्धांजलि पाने वाले पुरोधाओं में ऋषि विश्वामित्र, साध्वी सुलभा, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, महाराज इक्ष्वाकु, महाराज मांधाता, महाराज भगीरथ, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज अग्रसेन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रानी दुर्गावती, सम्राट हर्षवर्धन, महाराज सुहेलदेव, वीर कुंवर सिंह, अमर क्रांतिकारी बंधू सिंह, राणा वेणी माधव सिंह बैस, महाराज गंगा सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, राजा उदय प्रताप सिंह, राजा बलवंत सिंह, तिलकधारी सिंह, राजा युवराज दत्त सिंह और राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह रानी पद्मावती शामिल रहे।

भाजपा सबसे बड़ी सत्य विरोधी पार्टी, हर वर्ग से किया झूठा वादाः अखिलेश यादव

लखनऊ(संवाददाता) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि भाजपा सबसे बड़ी सत्य विरोधी पार्टी है, जो झूठे वादे करती है और सत्ता में आने के बाद हर वर्ग को धोखा देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आशा वर्कर, किसान, नौजवान, मजदूर और व्यापारी सभी से बड़े–बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने आशा वर्करों से भी किए गए वादों को पूरी तरह भुला दिया है। इसी कारण आशा बहनों के बीच भारी निराशा और गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि वादा खिलाफी करने के बाद भाजपा सरकार के शासन और प्रशासन से जुड़े लोग आशा बहनों को नीचा दिखाने के लिए गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो न केवल अपमानजनक है बल्कि आक्रोश को और बढ़ाने वाला है।

मनरेगा के लिए कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन

सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी कार्रवाई की मांग

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी। दिनांक 11 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर के अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास प्रदर्शन मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद पटेल की अगुवाई में किया गया । जिसमें जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तथा मनरेगा बचाओ संग्राम की कोऑर्डिनेटर शिप्रा अवस्थी अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित रहे स उपस्थित कांग्रेस जनों ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया । उक्त प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने मनरेगा को गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा बताया स उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों लोगों को रोजगार देती है जिससे उनके परिवारों का भरण पोषण होता है कांग्रेस ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने या इसके स्वरूप से छेड़छाड़ करने को जनहित के खिलाफ बताया । साथ ही पटेल ने यह भी बताया कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की देन है जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस योजना की पहचान बदलने का प्रयास करती है तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध आगे भी करेगी । मनरेगा बचाओ संग्राम की हमारी प्रमुख चार मांगे हैं काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी हो स काम के संवैधानिक अधिकारी की पूर्ण बहाली की जाए, न्यूनतम वेतन ₹400 किया जाए स नहीं तो यह संग्राम रुकने वाला नहीं । जिला कोऑर्डिनेटर शिप्रा अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि मनरेगा को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के आत्मसम्मान और रोजगार की गारंटी बताया स उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजनाओं के नाम बदलकर जनता को भ्रमित करना चाहती है स जबकि जमीनी स्तर पर रोजगार और मजदूरी के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है स उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा के अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का संकल्प दिलाया । उक्त कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता रवि तिवारी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी । उक्त प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रियाज अहमद मोनू, डॉ रईस अहमद उस्मानी, विपुल गुप्ता, के के मिश्रा अन्नू, वरिष्ठ कांग्रेसी इरफान किदवई, रामकुमार वर्मा, राजेश अवस्थी, जावेद अली, शाहजेंद्र दीक्षित, प्रेम वर्मा, अब्दुल कयूम, सुधीर शुक्ला, अनंत राम गौतम , राम शंकर पासी, मोहम्मद साबिर, अब्दुल जाफरी, राम सजीवन तिवारी मतीन आदि सैकड़ो कांग्रेसी उपस्थित रहे।

26 साल से जल रही अखण्ड आस्था की ज्योति, अखण्ड ज्योति के 26वें जन्मोत्सव पर झूमे भक्त,लगे जयकारे

लखीमपुर–खीरी।कहां जाता है कि कोई दीपक लगातार 24 वर्षो तक अखण्ड जलता रहे तो वह स्वतरू ही सिद्ध हो जाता है और ऐसे सिद्ध दीपक के दर्शन मात्र से ही अनेक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, जन्म–जन्मांतरों के अनेकानेक पापों का नाश हो जाता है एक ऐसा ही सिद्ध अखण्ड दीपक जनपद लखीमपुर–खीरी के प्राचीन तीर्थ स्थल देवकली के आश्रम में है जो पिछले 26 सालों से अखण्ड गाय के घी से जल रहा है कहा जाता है कि इस अखण्ड दीपक के सामने केवल एक मिनट खड़े रहकर जो भी कामना की जाती है वह पूर्ण होकर ही रहती है इस अखण्ड दीप के निकट श्री संत श्री भवानी प्रसाद उपाध्याय (नेपाली बाबा) का एक मनमोहन प्रतिमा भी स्थापित है हालांकि इस अखण्ड ज्योति के ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर एवं संध्या कालीन तीनों समय जप, ध्यान, साधना नियमित रूप से सम्पन्न होती है सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस अखण्ड ज्योति के दर्शन के लिए सैकड़ों लोग दूर–दूर से प्रतिदिन आते हैं और दिव्यता का अनुभव करते हैं इसी क्रम में आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को अखण्ड ज्योति का 26वां जन्मोत्सव महन्त प्रमोद जी महाराज के मार्गदर्शन में गुरुकुल के बटुक ब्रह्मचारियों(आश्रमवासियों), आचार्य सुधीर मिश्रा, आचार्य सत्यम मिश्रा, आचार्य अनिल शुक्ला, आचार्य प्रमोद अवस्थी,रमित मिश्रा श्रद्धालुओं ने बड़ी धूमधाम से पूजन, अर्चन,हवनादि कर मनाया गया। जिसमें प्रमुख रूप से अतुल गुप्ता, उमाशंकर महेंद्र,अशोक अवस्थी, त्रिभुवन लाल दीक्षित श्रीमती सुमन वर्मा,रानी चौधरी, सुशील कुमार शुक्ला,इन्दु मोहन मिश्रा,राम प्रकाश गुप्ता, राजेन्द्र वर्मा,राम जी पुरी,सुरेशचन्द्र गुप्ता,रजत श्रीवास्तव आदि श्रद्धालुओं ने पूजन–अर्चन हवनादि कर प्रसाद ग्रहण किया।

किसानों ने दिया चीनी मिल में धरना

गन्ना चेन पर बैठे किसान पेराई हुई ठप प्रबंधन पर शोषण का भी आरोप

लखीमपुर खीरी। बजाज ग्रुप की खंभारखेड़ा स्थित चीनी मिल में सोमवार को किसानों ने गन्ना चेन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस धरने के कारण चीनी मिल का संचालन और गन्ना पेराई पूरी तरह से ठप हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप

है कि चीनी मिल प्रबंधन मनमाने ढंग से गन्ना खरीद कर उनका शोषण कर रहा है। किसानों ने बताया कि कई बार गन्ना लेकर पहुंची उनकी ट्रॉलियों को बिना किसी ठोस कारण के फैक्ट्री से वापस भेज दिया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गन्ने का भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है। भुगतान में लगातार देरी से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन समस्याओं के कारण ही उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा।किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक गन्ना खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाती और बकाया भुगतान जल्द नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञात हो कि जनपद में बजाज ग्रुप की चीनी मिलों में गन्ना भुगतान को लेकर पिछले काफी समय से दिक्कतें बनी हुई हैं।धरने की सूचना मिलते ही मिल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वे किसानों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का धरना जारी था और मिल का संचालन बंद था।

एसआईआर संबंधी का हुआ आयोजन

लखीमपुर खीरी। दिनांक 11.01. 2026 को जिला पंचायत सभागार लखीमपुर खीरी में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र 'टेनी' रहे तथा कार्यक्रम का संचालन संजय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र 'टेनी' ने कहा कि 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जो ये एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरा करके मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका यह है कि जो लोग किसी त्रुटिवश इस मतदाता सूची से वंचित रह गए है। किसी कारण से उनका नाम छूट गया है या कोई नए मतदाता है उनका बनना है या विरोधी राजनैतिक दल ने कुछ ऐसे वोट बना दिया है जिनका वोट नहीं बनना चाहिए था ऐसी सारी त्रुटियों को सुधार करने का आपका 31 जनवरी तक का समय है। उसके लिए जो आवश्यक फार्म है उनके विषय में बहुत विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ना, नाम सुधार करना और फिर कोई ऐसे वोटर है जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए उनका निरस्तीकरण करना। इन सबके लिए अलग–अलग फार्म है। वोटर लिस्ट को देखकर करके उस फार्म को भर करके आप जो भी त्रुटि 6 जनवरी की वोटर लिस्ट में है उसको सुधार सकते है उसके लिए 31 जनवरी तक का समय आपके पास है। आज यह बैठक इसीलिए की गई है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर में जो वोटर कम हुए है उसमें पार्टी में चिंता का विषय यह है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर कम हुए है तो हम लोग इसका निरीक्षण जरूर करें हालांकि यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसका उद्देश्य यही है कि जो ठीक व सही वोटर है वह वोटर लिस्ट में रहे। यह कोई नया काम नहीं है और पहले शायद आप एसआईआर नाम भी सुने नहीं होगे। कभी इतनी चर्चा भी नहीं हुई होगी। वोटर लिस्ट का काम है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ते है हटते है, छूटते है लेकिन ऐसी चर्चा कभी नहीं होती थी कि जिससे एसआईआर पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा बन जाए जो एक राजनैतिक विषय के तहत बहुत से हमारे विरोधी दलों के द्वारा समय–समय पर उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जो इस देश में कभी हुआ न हो। हम सारे काम वहीं कर रहे है जो हमारे संविधान संवत् है जो किसी भी सरकार को करने चाहिए लेकिन वह सारे काम ऐसे होने चाहिए जिनके निमित्त वह आर्टिकल बने है एक्ट बने है धाराएं बनी है उसके लिए उनका उपयोग हो उनका दुरूपयोग न हो हमने सिर्फ इतना किया है पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलोसपी थी दर्शन था दर्शन कभी बदलता नहीं है फिलोसपी जब स्थापित होती है तो उसके जो सिद्धान्त होते है वह समय–समय पर हमेशा जैसी परिस्थितियां जैसा समय होता है उसके अनुरूप परिणाम देते है। भाजपा ने नया कुछ नहीं किया लेकिन पिछले 11 वर्षो में पूरे देश में जिस तरह का बदलाव आया जिस तरह का सकारात्मक परिवर्तन हुआ उससे देश में न केवल भाजपा की साख बढ़ी हमारे वोटर बढ़े है यही कारण है कि विरोधी राजनैतिक दल अनेको प्रयास करते है वो दुष्प्रचार करते है लेकिन उसके बाद भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है।

स कार्यक्रम में पवन गुप्ता ब्लाक प्रमुख नकहा, कुलभूषण सिंह जिला उपाध्यक्ष भाजपा, विश्वनाथ सिंह प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख फूलबेहड़, अरविन्द गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोंटी पाल, सभासद राकेश मिश्रा, पूर्व ब्लाक प्रमुख आशुतोष वर्मा, मनोज वर्मा पूर्व मंत्री भाजपा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविन्द सिंह 'संजय', पूर्व सांसद प्रतिनिधि जितेन्द्र त्रिपाठी 'जीतू' एड0, पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय मिश्रा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि मुन्ना लाल अवस्थी, पूर्व सांसद प्रवक्ता अम्बरीष सिंह, आर0पी0 कटियार अध्यक्ष भूमि विकास बैंक लखीमपुर, सतीश श्रीवास्तव, विपिन मिश्रा, अनुज शुक्ला 'बीटू', प्रदीप शुक्ला, पन्ना लाल अग्रवाल, डा0 बबलू गुप्ता, अशोक जायसवाल, संजय गिरि, सतीश चौधरी, वीरपाल मिश्रा, राहुल चौरसिया, सूरज पाण्डेय, भैय्या लाल तिवारी, अरूण कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बाघिन का कहर, महिला को उठा ले गई, गन्ने के खेत में मिला अधखाया शव

लखीमपुर खीरी। नरभक्षी बाघिन का आतंक बढ़ता जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में चारा काट रही महिला को बाघिन उठा ले गई। 12 घंटे बाद गन्ने के खेत में महिला का अधखाया शव मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। शाम ढलते ही खौफ ने लखीमपुर खीरी के एक गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जंगल से सटे इलाके में चारा काट रही एक महिला को नरभक्षी बाघिन अचानक उठा ले गई। पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद अगली सुबह गन्ने के खेत से महिला का अधखाया शव बरामद हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण सहमे हुए हैं। घटना शनिवार शाम की है, जब दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित निघासन वन रेंज के थाना तिकुनियां क्षेत्र के महाराज नगर गांव में यह हादसा हुआ। वन विभाग के अनुसार, नरभक्षी बाघिन अपने दो शावकों के साथ शिकार की तलाश में आबादी वाले इलाके में आ गई थी। इसी दौरान उसने खेत के पास चारा काट रही महिला पर हमला कर दिया।मृत महिला की पहचान 35 वर्षीय ऊषा देवी के रूप में हुई है। वह अपनी पड़ोसी 32 वर्षीय गूंधगूंनी देवी के साथ शनिवार की शाम जंगल से सटे क्षेत्र में चारा काट रही थी। गूंधगूंनी देवी के मुताबिक, अचानक बाघिन ने ऊषा देवी पर हमला किया, उसकी गर्दन दबोचकर उसे गन्ने के खेत की ओर खींच ले गई। यह देख वह घबराकर भागी और शोर मचाया।घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे रेंजर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने रात भर कांबिंग ऑपरेशन चलाया। रविवार सुबह उसी गन्ने के खेत से ऊषा देवी का अधखाया शव बरामद किया गया महिला की मौत की खबर फैलते ही महाराज नगर गांव सहित आसपास के कई गांवों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही और जंगली जानवरों की सही ट्रैकिंग न होने के कारण ऐसी घटनाएं बार–बार हो रही हैं। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।वन विभाग की टीमें पगमार्क के सहारे नरभक्षी बाघिन का पीछा कर रही हैं। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगल व खेतों की ओर अकेले न जाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बाघिन को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है, ताकि किसी और जान का नुकसान न हो।

जिले की आठों विधानसभा में बीएलओ ने पढ़ी आलेख्य निर्वाचक नामावली

सभी बूथों पर सूची पढ़ी गई, राजनीतिक दलों और मतदाताओं ने रखी निगरानी

लखीमपुर खीरी, 11 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर आलेख्य निर्वाचक नामावली को बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आम मतदाता मौजूद रहे, जिन्होंने हर नाम पर कड़ी नजर रखी। जिले की विधानसभा क्षेत्र 137– पलिया, 138–निघासन, 139– गोला, 140– श्रीनगर, 141– धौरहरा, 142– लखीमपुर, 143– कस्ता और 144– मोहम्मदी के सभी बूथों पर यह प्रक्रिया पूरी हुई। बीएलओ ने प्रत्येक बूथ पर विवरणवार मतदाता सूची पढ़कर सुनाई, ताकि किसी भी त्रुटि या अभाव की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और जरूरत पड़ने पर सुधार हेतु सुझाव भी दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से लागू की गई। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और मतदाता अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। लखीमपुर खीरी पहुंचे एडी बेसिक, मतदेय स्थलों का किया निरीक्षण विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत रोल आब्जर्वर के निर्देशन में अपर निदेशक (बेसिक शिक्षा) एसके तिवारी ने जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचकर 142–लखीमपुर, 140–श्रीनगर और 143–कस्ता विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीएलओ आलेख प्रकाशित नामावली पढ़ते पाए गए। साथ ही संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारी भी मौजूद रहे।

आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 12 जनवरी को ऊर्जा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचेगा कर्मचारी संघ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए बिजली आउटसोर्स कर्मचारी 12 जनवरी को ऊर्जा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा अपने ही आदेशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से लगभग 15 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की गई है। इसके अलावा 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिनांक 18 सितंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए कार्य के अनुरूप अनुबंध नहीं किया जा रहा है, न ही 18 हजार रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को अब तक कार्य पर वापस नहीं लिया गया है। प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज नहीं कराया जा रहा और उपचार में खर्च की गई धनराशि का भुगतान भी संविदाकारों के बिल से काटकर नहीं किया जा रहा।

इसके साथ ही जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के बावजूद भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित नहीं की गई है तथा मनमाने ढंग से कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने की स्थिति में कर्मचारियों को कार्य से हटाए जाने का भी भय बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं के समाधान को लेकर संगठन द्वारा लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण संगठन ने 12 जनवरी को लखनऊ स्थित ऊर्जा मंत्री के आवास पर आयोजित जनता दरबार में पहुंचकर अपनी मांगें रखने का निर्णय लिया है।

इस जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पीड़ित बिजली आउटसोर्स कर्मचारी भाग लेंगे।

मेडिकल डिवाइस पार्क में 22 भूखंड की योजना

नोएडा)। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने के इच्छुक कंपनियों के लिए अच्छा मौका है। प्राधिकरण ने 22 भूखंडों की योजना शुरू की गई है। इसमें 12 जनवरी से आवेदन किया जा सकेगा। आखिरी तारीख 11 फरवरी है। यीडा सिटी के सेक्टर–28 में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां मेडिकल उपकरण से संबंधित कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाने है। अब तक 101 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से एक कंपनी कार्यशील हो चुकी है। बाकी को मौके पर कब्जा दिया जा चुका है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक 1000, 2100 और 5940 वर्गमीटर के 22 भूखंडों की योजना है। इसमें सबसे ज्यादा 11 भूखंड 1000 वर्गमीटर के हैं। वहीं, 2100 वर्गमीटर के नौ और 5940 वर्गमीटर के दो भूखंड हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से किए जा सकेंगे। बता दे मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। लॉजिस्टिक्स और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ मेडिकल डिवाइस के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल–मेडिकल डिवाइस (ईपीसी–एमडी) के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड डिजिटल आईटी सेटअप तैयार किया जा रहा है।

नोएडा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद,

नोएडा,11 जनवरी 2026 (यूएनएस)। नोएडा में ठंड और कोहरे के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिले में स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। नए साल की शुरूआत से ही गौतमबुद्ध नगर में स्कूल ठंड के कारण अभी तक नहीं खुल पाए हैं। यह आदेश गौतमबुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर लगातार पड़ रही ठंड और कोहरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले, स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई थीं। नए आदेश के बाद अब ये छुट्टियां 15 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। नव वर्ष 2024 शुरू होने के बाद से गौतमबुद्ध नगर में ठंड और कोहरे के कारण स्कूल लगातार बंद हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि किसी स्कूल द्वारा आदेशों का उल्लंघन कर उसे खोला जाता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि इन दिनों उत्तर–पश्चिमी हवाएं 10–12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जिसकी वजह से गलन बरकरार है। अगले 4–5 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। इस हफ्ते बारिश होने की संभावना नहीं है। दोपहर में धूप खिली रहेगी, जबकि सुबह और शाम ठंड का असर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते शनिवार को तापमान में 3–6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खिली धूप ने ठंड से राहत दी और कोहरे का असर भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी इसी तरह का खुशगवार मौसम रहने के आसार हैं। हालांकि सोमवार से एक बार फिर तापमान में कमी के साथ सर्दी दस्तक देगी और अगले कुछ दिनों तक सर्दी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को सुबह तराई क्षेत्र में कहीं–कहीं घना कोहरा रहा तो बाकी जगहों पर भोर में हल्का से मध्यम कोहरा रहा। दिन चढ़ने के साथ ही जल्द ही कोहरे का असर कम हो गया और तेज धूप ने ठंड से काफी राहत दी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति और दिशा में हुए परिवर्तन की वजह से प्रदेश में रविवार तक मौसम शुष्क रहेगा।

महिलाओं के लिये प्रेरक रही आजीविका विकास कार्यशाला

सक्षम भारत पुरस्कार से सम्मानित हुई हुनरमंद युवती महिलाओं सहित 35 हस्तियां तोशानी, मंजरी, रितु, शुभांगी व अनिता ने बताये व्यावसायिक गुर

लखनऊ, 11 जनवरी। लेट्स गिव होप फाउण्डेशन की ओर से यहां संत

गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह गोमतीनगर में हुनरमंद और प्रेरक प्रोफेशनल्स को सक्षम भारत पुरस्कार–2026 से नवाजा गया। इस मौके पर चली कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिलाओं के लिये आजीविका विकास के अवसर विषय और कौशल पर विचार रखकर उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया। यहाँ सक्षम भारत पुरस्कार पाने वालों में शिक्षाविद् मंजू सिन्हा नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. प्रोफेसर डा.पूजा कानोडिया, कथक नृत्यांगना रतन सिस्टसर्स ईशा–मीशा रतन, अयोध्या की गायिका व गीतकार संजोली पांडे, स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर ट्रस्ट की डा.आशा सिंह, व्यवसायी अर्चना मिश्रा, सार्वजनिक भाषण विशेषज्ञ कविता चौबे कंपनी सेक्रेटरी व हस्तशिल्पी प्रीति शर्मा, शिक्षिका डॉ. आफिया बानो, सरिता गौतम, संज्ञा शर्मा, रिजवाना परवीन, समाजसेवी पूनम कुमारी, अंजलि श्रीवास्तव और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर दीक्षा सैनी प्रमुख महिला विभूतियां रहीं। इसके अलावा प्रीति कश्यप, वंशिता रावत, अनीता सरोज, शिवानी प्रजापति, सिमरन यादव, शालिनी कश्यप, प्रियंका पाल, आकांक्षा तिवारी, अनीशा बिष्ट, प्रज्ञा साहू, शबाना, मान्या सिंह, नागेंद्र, वसन गिरि, हिमांशु सिंह, अजय भी सम्मानित हुए। इनके साथ ही केजीएमयू के डा. गौरव मिश्रा, व्यवसायी विशाल सिंह, सहायक प्रोफेसर कुणाल दीक्षित, स्टेट ला ऑफिसर हाईकोर्ट शिव प्रसाद कुशवाहा, सोशल ऑडिट कमेटी सदस्य कुंदन सैनी, सीनियर आई कन्सलटेन्ट स्टोरी टेलर जीतेश श्रीवास्तव को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। मानसी शर्मा व प्रियांशी के गणेश वंदना नृत्य से प्रारम्भ हुए समारोह में फाउण्डेशन के संस्थापक अध्यक्ष आशीष मौर्या ने गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश भर में सक्षम स्किल सेंटर स्थापित करके मध्यम एवं निम्न वर्ग की महिलाओं और युवाओं को कौशल परख शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

कार्यशाला में जरी जरदोजी चिकनकारी विशेषज्ञ तोशानी, मेकअप आर्टिस्ट मंजरी जायसवाल, ग्राफिक व वीडियो एडिटर रितु पांडे, फोटोग्राफर शुभांगी मौर्य और नवाचारी शेफ अनिता शर्मा ने अपने अनुभव साझा किये। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाएं अपने कौशल को पहचानकर व्यवसाय में बदल सकती हैं और घर से ही सफलता प्राप्त कर सकती हैं। वक्ताओं ने व्यावहारिक व्यावसायिक युक्तियां भी समझायीं जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर सकती हैं। कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं ने वक्ताओं से सवाल पूछे और अपने अनुभव साझा किये। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सत्र रहा। इस अवसर पर संस्था की गतिविधियों

यूपी में अप्रैल से लागू होगा नया लेबर कोड बिल

लखनऊ। केंद्र सरकार का नया लेबर कोड बिल अप्रैल से उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। नए बिल को अंगीकार करने के लिए राज्य की आवश्यकता के अनुसार श्रम विभाग ने मामूली बदलाव कर संशोधित बिल विधि विभाग भेज दिया गया है। जनवरी में लेबरकोड बिल प्रकाशन कर सरकारआपत्तियां मांगेगी। 45 दिन बाद जरूरी आपत्तियों में सुधार कर बिल को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। नए बिल का अनुपालन अनिवार्य हो जाएगा।29 सेंट्रल कोड सरकार ने समेटकर चार कोड में कर दिया है। इसे बीते साल 21 नवंबर को सरकार ने लागू कर दिया है। बिल राज्यों में लागू करने के लिए सरकार ने 90 दिन का समय दिया था। 22 दिसंबर को चार कमेटियों का गठन किया था जिसे 27 दिसंबर तक रिपोर्ट देनी थी। कमेटियों की रिपार्ट के आधार पर बीते 9 जनवरी को श्रम विभाग ने बिल को मामूली बदलावों के साथ विधि विभाग को करेक्शन के लिए भेज दिया है। केंद्र के विभागों में केंद्रीय बिल के नियमों और राज्य के विभागों में राज्य के नियमों का अनुपालन कराया जाएगा।नए लेबर कोड बिल में कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। कंपनी कर्मचारी की नियुक्ति स्थाई, अस्थाई, संविदा, दिहाड़ी या आउटसोर्सिंग किसी भी रूप में करती है तो नियुक्ति पत्र देने की बाध्यता होगी। अभी कंपनियां नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी करतीं हैं। नियुक्ति पत्र में सेवा शर्तों के साथ वेतन की जानकारी लिखी होगी। ग्रेच्युटी के लिए फिक्स टर्म इंप्लॉयमेंट का प्रावधान बनाया गया है। कोई कर्मचारी जितने दिन काम करेगा उतने दिन की ग्रेच्युटी कर्मचारी को देनी होगी। ईपीएफ, ईएसआई का लाभ देना होगा।कंपनियां ईपीएफ में हिस्सेदारी से बचने के लिए अपने कर्मचारियों का बेसिक पे कम रखतीं हैं। जबकिकर्मचारियों का वेतन बेसिक पे का कई गुना अधिक होता है। नए बिल में कुल सैलरी का आधा बेसिक पे रखने की बाध्यता की गई है। श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बेसिक पे बढ़ने से किसी कर्मचारी की इन हैंड सैलरी में कोई असर नहीं पड़ेगा। 40 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी कंपनी को हर साल कराना होगा।अभी देश के अलग–अलग राज्यों में फैक्ट्री खोलने के लिए अलग–अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन अब नई व्यवस्था में एक ही लाइसेंस पूरे देश में मान्य होगा। कोई उद्यमी अपना कारोबार देश के विभिन्न राज्यों में खोलना चाहता है, ।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक
आरती पाण्डेय
eks-
9807059191- 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।